BSF Aircraft Crash

1112. SHRIMATI KAMALA SINHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be please to state :

(a) whether a BSF aircraft crashed, recently, at the IGI airport, Delhi killing the BSF Inspector General;

(b) if so, what are the details of the outcome of the inquiry conducted by Government into the mishap; and

(c) what action has been taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Central Government has appointed a Committee of Inquiry under the Aircraft Rules, 1937. The Inquiry has tion in the Kashmir Valley;

Discussion on Jammu and Kashmir

1113. DR. RAMENDRA KUMAR YADAV 'RAVI' : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a high level meeting chaired by him was held in Jammu and Kashmir during June, 1992 to review the situation in the Kashmir Valley;

(b) if so, what were the issues discussed and also the suggestions and recommendations made therein; and

(c) what follow up action is being taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) :

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) In the meeting with officials, discussions on the overall situation in the State, including the efforts to contain terrorism, bringing about greater involvement of the people, matters concerning development of the State and problems of Kashmir migrants were held. The Government of Jammu & Kashmir has stepped up its efforts in these directions.

नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई योजना

1114. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार इस विचार का समर्थन करती है कि नक्सलवाद की समस्या मात्र कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है बल्कि बहुत से जटिल आर्थिक और सामाजिक पहलू भी इससे जुड़े हुए हैं :

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए केन्द्र को कोई कार्रवाई योजना भेजी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इस कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार कोई वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए प्रदान की जाने वाली राशि कितनी होगी तथा यह सहायता कब तक प्रदान की जायेगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने प्रभावित जिलों के लोगों को तुरन्त राहत उपलब्ध कराने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है । योजना पांच वर्ष की अवधि के लिए तैयार की गई है तथा विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 71875.37 लाख रुपये की कुल आवश्यकता है । इस बारे में इस मंत्रालय में विचार-विमर्श किया गया था, यह निर्णय लिया गया कि प्रभावित राज्यों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं की संयुक्त समन्वय समिति (जे० सी०सी०) द्वारा जांच की जायेगी तथा उसके बाद संबंधित सरकारों द्वारा

अपनी आठवीं योजना प्रस्तावों में उसका समावेश किया जायेगा। योजना आयोग द्वारा राज्यों की योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय इन प्रस्तावों पर अनुमोदित केन्द्रीय सहायता फार्मूलों के भीतर विचार किया जायेगा।

नक्सलवाद से निपटने के लिए प्रयास

1115. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1991 में केन्द्रीय गृह मंत्री जी द्वारा नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी और क्या उस बैठक में यह निर्णय किया गया था कि नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए सभी राज्यों को समन्वित प्रयास करने होंगे ;

(ख) नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए किन-किन राज्यों को कितने-कितने केन्द्रीय बल उपलब्ध कराए गए हैं ;

(ग) यदि राज्य सरकार को अभी तक केन्द्रीय बल उपलब्ध नहीं कराए गए हैं तो इन्हें कब तकउपलब्ध करा दिया जाएगा ;

(घ) क्या नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय बल उपलब्ध कराने और विभिन्न पुलिस संगठनों में प्रदेश के पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने की भी मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो अभी तक प्रदेश सरकार को कितने केन्द्रीय बल उपलब्ध कराए गए हैं और प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की कुछ कम्पनियां, नक्सलवादी समस्या से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई हैं। उनकी तैनाती की प्रकृति का निर्णय राज्य सरकार को लेना है । मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से, नक्सलवाद-विरोधी अभियानों के लिए अर्द्ध सैनिक बलों की अतिरिक्त कम्पनियों के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। तथापि, देश में अन्यत्र तैनाती के वादे के कारण, अतिरिक्त तैनाती के बारे में राज्य सरकार के अनुरोध को माना नहीं जा सका। जहां तक विभिन्न केन्द्रीय पुलिस संगठनों में मध्य प्रदेश राज्य के पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण का संबंध है, केन्द्रीय पुलिस संगठनों ने विभिन्न "पाठ्यक्रमों" में पुलिस-कर्मियों को नामित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को लिखा है। फिर भी केन्द्रीय पुलिस संगठनों द्वारा उन्हें आवंटित स्थानों का राज्य सरकार ने पूरा उपयोग नहीं किया है।

Removal of Jhuggi-Jhompris from the Vicinity of MPs Bungalows and Flats

1116. SHRI GAYA SINGH :
SHRI N. E. RALARAM :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether NDMC/MCD authorities have received any instructions from the House Committee of Lok Sabha to remove all the jhuggi-jhompris from the vicinity of MPs bungalows and flats with immediate effect; and

(b) if so, what action has been taken by the NDMC/MCD authorities in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB) : (a) and (b) The House Committee at its meeting held on 21-9-1992 desired that problem of jhuggies existing in VIP areas should be dealt with differently from the similar problem of city area and these should be removed within 30 days i.e. by 21-10-1992.